SHRI E. AHAMMED: Mr. Chairman Sir, I have a long list of work in progress in Rajasthan and also the work completed in Rajasthan. If you permit me it will be made available to the hon. Member.

Global recession in international market

*403. SHRI RAJEEV SHUKLA:††
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether Government is working out a Rs. 62,000 crore financial plan for micro, small and medium enterprises to gain an edge in the international market, as many enterprises have closed down in the United States and European Union in the wake of global recession;

(b) if so, what are the details of the plan;

(c) whether Skill Development Corporation has been set up with Rs. 1000 crore corpus to be topped up every year; and

(d) whether a national fund has been set up for the unorganized sector with a corpus of more than Rs. 1000 crore?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI DINSHA J. PATEL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) There is no specific financial plan of Rs. 62,000 crore for the micro, small and medium enterprises (MSMEs). For the promotion and development of MSMEs and to enhance their competitiveness, the Government is implementing a number of schemes/programmes, which include the National Manufacturing Competitiveness Programme and schemes relating to credit, infrastructural development, technology upgradation, marketing, entrepreneurial/skill development, etc. The Government and the Reserve Bank of India have also taken several recent measures to augment the credit flow to the MSMEs to address their credit needs.

(c) To coordinate and stimulate skill development efforts, the National Skill Development Corporation (NSDC) has been constituted as a "not for profit" company under Section 25 of the Companies' Act, 1956 with an initial authorised capital of Rs. 10 crore. In addition, the National Skill Development Fund (NSDF) has been registered as a Trust under the Indian Trusts Act, 1982 to act as a receptacle for contributions from Government/multilateral and bilateral agencies/private sector organisations. A sum of Rs. 995.10 crore has been transferred from the Government Budget to the NSDF, in order to fund the schemes/programmes forwarded by the NSDC.

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajeev Shukla.

(d) A Fund for the Unorganised Sector with a corpus of Rs. 1,000 crore is under consideration.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, if I go through the reply of the Minister, he has said that there is no specific financial plan to support the micro, small and medium enterprises. But at the same time, he has said that several measures are being taken to enhance the competitiveness of the sector. I want to know from the hon. Minister because of global recession this is one area which is hardly hit. So, which are the major sectors in this area where actually recession has hit and what steps Government is planning to take to improve the situation?

श्री दिन्शा जे. पटेल: माननीय सभापति जी, वैसे तो यह प्रश्न वित्त मंत्रालय के आधार पर पूछा गया है और कोलकता से निकलने वाले अखबार Financial Express में छपा है, उस के ऊपर से यह प्रश्न पूछा गया है। मेरे डिपार्टमेंट का तो इस से कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात कही है तो उस में बहुत से उपाय सोचे गए हैं। सभापति जी, आज 2001-2002 के आंकड़ों के मुताबिक उद्यमों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख है, रोजगारों की संख्या 4 करोड़ 20 लाख है, उत्पादन में योगदान 39 प्रतिशत है, निर्यात में योगदान 31 प्रतिशत है और जी.डी.पी. में योगदान 6 प्रतिशत है, लेकिन अभी 2006-2007 के आंकड़ों के मुताबिक उद्यमों की संख्या 2 करोड़ 7 लाख और रोजगारों की संख्या 5 करोड़ 90 लाख है। उस में बढ़ावा होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर रोजगार सृजन योजना और रिजर्व बैंक के साथ मिलकर यह योजना बनायी गयी है।

श्री राजीव शुक्ल: आप कृपया यह बताएं कि कौन-कौन से क्षेत्र, कौन-कौन से उद्योग प्रभावित हुए हैं?

श्री दिन्शा जे. पटेल: सभापति महोदय, गेम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, आभूषण, रत्न, diamonds, leather, furniture, automobiles के उद्योग प्रभावित हुए हैं और जो export oriented items ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस की वजह से 16.6 परसेंट डॉलर्स भी कम मिले हैं।

श्री राजीव शुक्ल: मान्यवर, भारतीय बाजार चीनी सामान से पटे पड़े हैं और उस का सब से ज्यादा असर लघु उद्योगों पर पड़ रहा है। महोदय, छोटे-छोटे manufacturers सब से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन का मंत्रालय इस बारे में Commerce Ministry से बात करेगा कि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और जो चीनी सामान भारतीय लघु उद्योग को प्रभावित कर रहे हैं, उन के ऊपर रोक लगायी जाए?

श्री दिन्शा जे. पटेल: माननीय सभापति महोदय, वैसे तो 60 साल के बाद भी आज लोगों की परदेशी माल, यू.एस.ए. मार्का, made in England मार्का सामान में ज्यादा रुचि होती है। Made in India वाला सामान लोगों को, सभी को कम रुचिकर लगता है। सर, चाइना वाली बात भी है ...(**व्यवधान**)...

श्री साबिर अली: सर, ऐसा नहीं है। यह सही नहीं है ...(**व्यवधान**)...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, this is not the fact. There are many people who prefer Indian goods. मंत्री जी, आप के पास लोगों की सोच का सही अनुमान नहीं है ....(**व्यवधान**)... Maybe, he can speak for the Government. He cannot speak on behalf of the people. ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए।

श्री दिन्शा जे. पटेल: मैं आप को नहीं कह रहा हूं। मैं लोगों की रुचि बता रहा हूं कि आज लोग ...(**व्यवधान**).... मैं भी लोगों में से आता हूं ...(**व्यवधान**)... मुझे भी लोग चुनकर भेजते हैं।

श्री सभापति: प्लीज, आप बैठ जाइए।

श्री दिन्शा जे. पटेल: मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं तो लोगों की सोच से ही आता हूं न। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर पुंज: सर, वे सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट दे सकते हैं, लोगों की तरफ से यह ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज ...(**व्यवधान**)... Please allow the answer to proceed ...(**व्यवधान**)... प्लीज, प्लीज।

श्री विक्रम वर्मा: यह लोगों की तरफ से कैसे कह सकते हैं।

श्री दिन्शा जे. पटेल: सर, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि * मैं यह इसलिए कह रहा हूं और अगर आप को इस में कोई बात गलत लगे तो इस को नहीं मानिए। ...(**व्यवधान**)... मैं वही कह रहा हूं। मुझे सुनिए ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please answer the question.

श्री विक्रम वर्मा: सर, मंत्री जी अपनी सोच लोगों पर नहीं थोप सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सी.पी. ठाकुर: सर, इसे delete कराइए।

MR. CHAIRMAN: Whatever is inappropriate will be deleted.

MR. CHAIRMAN: The Leader of Opposition.

SHRI ARUN JAITLEY: If you kindly analyse the Minister's reply, the Minister is saying that India is a perpetual violator of intellectual property of other countries. We have a city called * This is going to be used against us on various international fora. Your Minister has admitted on the floor of the House, 'we are perpetual violator of IPR.' ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: प्लीज़, आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ARUN JAITLEY: This is no trivial manner of answering questions. ...*(Interruptions)*...

श्री दिन्शा जे. पटेल: जेटली साहब, मैं तो Short Form बोल रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Will you allow the House to proceed? ...*(Interruptions)*... आप सिर्फ इनके सवाल का जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)... Please. ...*(Interruptions)*... जो सवाल पूछा गया है, आप केवल उसका जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिन्शा जे. पटेल: सदस्य ने चाइना की बात की है तो मैं यही बता रहा हूँ कि anti-dumping के लिए जो application आती है, उसके बारे में Ministry of Commerce जरू र सोचती है और अगर ऐसी बात हमारे पास आयेगी तो भी हम Commerce Ministry से बात करके उसके बारे में आगे कुछ करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Chairman, Sir, the Minister's remarks must be expunged. ...*(Interruptions)*... They can't go on record. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The Chair will look at the remarks and if inappropriate, due action will be taken.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Chairman, Sir, in the Indian economy, the small, medium and micro enterprises have a very important role to play. In fact, during the unprecedented global crisis in the economy, our hon. Prime Minister gave a call to the entire Indian industry to convert global crisis into an opportunity for India. So, I would like to know in this background, keeping in view the hundred days' target, what efforts he is going to make so that small-scale, medium and micro enterprises would be able to achieve the best results. Though banking sector doesn't come under him, but it is his responsibility to involve the Finance Ministry and the banking sector to give more help to the medium and minor enterprises. Sir, normally, from the reports what we see is that they give assistance only to the big industrialists, big people and not to the small people. So, you must make an effort to see that they give assistance to small people also. This is what I want to know.

श्री दिन्शा जे. पटेल: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो बताया है, उसके बारे में भी कोशिश की गई है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना जो 2009-10 में शुरू की गई है, उसमें भी भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2008-09 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को लगभग 64000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लोन मिला है, जोकि 25.7 परसेंट की वृद्धि दर्शाता है। जो पहले सूक्ष्म उद्योगों को दिया जाता था, अब मध्यम उद्योगों को भी 24000 करोड़ रुपये ज्यादा दिया गया है। प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यह योजना सभी स्टेट्स में लागू हो। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 10 परसेंट, इनवेस्टमेंट के सामने परियोजना की सब्सिडी 15 परसेंट है और यह ग्रामीण क्षेत्र में 25 परसेंट है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 परसेंट, इनवेस्टमेंट पर 25 परसेंट सब्सिडी और गांवों में 35 परसेंट की सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार, उनको बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश की जाती है।

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I have seen the reply given by the hon. Minister. I admit that skill development is of dire necessity. The Government has created the National Skill Development Council. But the Government is not depending on this. It is transferring the responsibility of this Government Corporation to a trust called NSDF. The first part of my supplementary is, why do they do so?

MR. CHAIRMAN: Only one supplementary, please.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I am raising only one supplementary. Why is there no scheme to provide the skill development skills in the large North-Eastern region so far as the khadi and village Industry is concerned.

श्री दिन्शा जे. पटेल: माननीय सभापति महोदय, कौशल विकास प्रयासों के समन्वय एवम उन्हें प्रेरित करने के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 10 करोड़ रुपए की आरम्भिक प्राकृतिक पूंजी से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का "लाभ हेतु नहीं" कम्पनी के रूप में गठन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास फंड को भी भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत सरकार बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र संगठनों से अंशदान प्राप्ति कर्ता के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकृत किया गया है। एनएसडीसी द्वारा अग्रेषित योजनाओं ...(**व्यवधान**)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, he has repeated the same thing that is ... *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please. He is answering a question. *...(Interruptions)...*

SHRI MATILAL SARKAR: There is a Government corporation. *...(Interruptions)...*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, he is repeating the same thing that is given in the statement. *...(Interruptions)...*

श्री दिन्शा जे. पटेल: सर, कम्पनी एक्ट के आधार पर यह किया गया है और उसमें सरकार तथा और लोग भी जुड़ सकें, इसलिए 51:49 की वजह से यह किया गया है। अगर 51% हो जाएगा तो सरकारी हो जाएगा, निजी लोगों को इसमें कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। इसलिए निजी लोगों को साथ जोड़ने के लिए कम्पनी एक्ट की वजह से 49:51 से यह काम किया जाता है।

DR. (SHRIMATI) KAPILA VATSYAYAN: Mr. Chairman, Sir, this is apropos of the reply given by the Minister that Indians prefer foreign goods. May I ask the Minister whether there is any statistical report on the preference of Indians for foreign goods and a *tilaanjali* of all that Mahatma Gandhi, Kamala Devi Chattopadhyaya and Rukmani Devi stood for? And, do the Members of the Rajya Sabha wear only imported clothes? *...(Interruptions)...*

श्री दिन्शा जे. पटेल: सभापति महोदय, माननीय सदस्या का प्रश्न वैसे तो इससे relevant ही नहीं है। इसके साथ यह relevant नहीं है ...(**व्यवधान**)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: It is relevant to the statement made by you. *...(Interruptions)...* It is totally relevant. *...(Interruptions)...*

श्री बलबीर पुंज: सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो वक्तव्य ...(**व्यवधान**)...

श्री दिन्शा जे. पटेल: अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर माननीय सदस्या मुझे नोटिस देंगी तो मैं जानकारी उन्हें दे दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: श्री महेन्द्र मोहन।

श्री बलबीर पुंज: सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है ...(**व्यवधान**)... बिल्कुल relevant है।

श्री महेन्द्र मोहन: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौशल विकास प्रयासों के लिए जो कम्पनी बनाई गई है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास फंड, इससे जो सहायता दी जा रही है, उससे कितने उद्योगों को उन्होंने पुनर्जीवित किया है? क्योंकि, सवाल वहीं पर आ जाता है कि implementation part पर कोई कार्य नहीं होता, केवल इन्हें बना दिया जाता है। 1,000 करोड़ रुपए के कॉरपस की निधि विचाराधीन है, तो यह कब से विचाराधीन है, यह बतलाने का कष्ट करें?

श्री सभापति: आप कृपया एक ही सवाल पूछिए।

श्री महेन्द्र मोहन: मेरे एक ही सवाल के दो भाग हैं कि यह जो निधि बनाई जा रही है, यह निधि कब तक बना दी जाएगी और जो कम्पनी बनाई गई है, उससे कितने उद्योगों को, कितने number of industries को लाभ पहुंचाया गया है, जिससे कि उनका पुनरुद्धार हो सके और वे अपनी स्ट्रीमलाइन में प्रोडक्शन पर आएं?

श्री दिन्शा जे. पटेल: सर, Tailoring and Readymade Garments का percentage 14.71% है, Food Products का 12.41%, Fabricated and Metal Products 8.5%, वस्त्र 6.49%, Furniture 5.69%, Machinery Equipment 4.9% और जो पहले बताया गया है, उद्योगों की बात की गई है तो रिज़र्व बैंक और SIDBI के साथ बात करने के बाद जो हुआ, उससे भी उद्योगों में बढ़ावा आया है। 2007 में जो बंद उद्योग थे, उनकी संख्या 1,32,081 थे, मगर इन सभी प्रयासों की वजह से 2008 में उनकी संख्या 99,941 रह गई और इसमें 28% की कमी हुई है। इसलिए कौशल जो बनाया है, उसमें भी जैसा मैंने बोला कि 4.9 और 5.1 के प्राइवेट की वजह से करीब 10 करोड़ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास फंड भी दिया गया है, इससे हमारा जो माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग है, उसमें बढ़ावा होगा और इसी तरीके से यह योजना एप्लाई हो जाएगी।

Failure of NRHM in achieving targets

*404. PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:††
SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the National Rural Health Mission (NRHM) has failed to achieve its targets in the last few years;

(b) if so, the factors responsible therefor: and

(c) the manner in which the various targets are sought to be achieved during the current year?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No. In fact the success of the National Rural Health Mission (NRHM) has been validated not only through internal monitoring systems but also through external Surveys and Review Missions. **In fact the Second Common Review Mission has confirmed that NRHM has** galvanized the public sector health system in every State, leading to higher Out Patient Department cases (OPD), In Patient Department cases (IPD), institutional delivery and improved coverage of immunization, diagnostics and ambulance services.

(b) Does not arise.

(c) The achievement of a programme has to be seen on outcome indicators, process indicators, physical and financial progress over a given period. On all of these parameters, the performance of the NRHM over the last four years has been very positive. This is confirmed by external validation by the Registrar General of India and the District Level Household and Facility Survey carried out by the International Institute for Population Sciences, Mumbai, in 2007-08.

The status in brief is as follows:—

---

††The question was actually asked on he floor of the House by Prof. Alka Balram Kshatariya.